



DAY 32°
NIGHT 28°
Hi Low

संक्षेप

महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर ईटक्लब के आउटलेट का लाइसेंस निलंबित

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और संचालन संबंधी कई गंभीर खामियां पाए जाने के बाद मुंबई स्थित ईटक्लब ब्रांड्स के एक आउटलेट का खाद्य लाइसेंस तत्का

प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एफडीए ने बताया कि यह कार्रवाई 2 सितंबर से प्रभावी है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की गई है। संबंधित ईटक्लब आउटलेट गोरगांव पूर्व स्थित रॉयल पाम्स, आर मिल्क कॉलोनी में है। यह कार्रवाई केवल इसी प्रतिष्ठान पर लागू होगी और कंपनी के अन्य आउटलेट इससे प्रभावित नहीं होंगे। ईटक्लब के अंतर्गत बॉक्स और मोजो फ्रिज्जा समेत कई लोकप्रिय फूड ब्रांड संचालित होते हैं। एफडीए द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, निरीक्षण के दौरान आउटलेट में खाद्य पदार्थों, पैकेजिंग सामग्री और रसायनों के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। इसके अलावा परिसर में खराब स्वच्छता, हाथ धोने की उपर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की कमी तथा कीट नियंत्रण व्यवस्था में खामियां भी सामने आईं। निरीक्षण टीम ने पाया कि पीछे के दरवाजे से कीटों और हूले के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। साथ ही खाद्य तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की खाद्य सुरक्षा खतरों के लिए ठीक से जांच और सफाई भी नहीं की जा रही थी। एफडीए के अनुसार, खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारियों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे फ्रॉन, दस्ताने, हेडगियर और शु-कवर उपलब्ध नहीं थे। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मेडिकल जांच से जुड़े रिकॉर्ड भी अधूरे पाए गए।

चीनी मिलों के लिए राहत पैकेज, सरकार लाएगी 2,000 करोड़ की आसान ऋण योजना

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहकारी चीनी मिलों के लिए आसान लोन योजना और बाय प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जाएगी। सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक स्थिरता देने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार केंद्र सरकार की पॉलिसी के आधार पर एक सॉफ्ट लोन स्कीम शुरू करने जा रही है। डिटी सीएम सुनेश पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के सामने तुरंत एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करें। प्रस्तावित योजना के तहत, योग्य सहकारी चीनी मिलों को लगभग 2,000 करोड़ का कम ब्याज वाला सॉफ्ट लोन फंड मिल सकेगा। इन लोन को चुकाने के लिए 7 साल का समय मिलेगा और राज्य सरकार सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए का ब्याज का बोझ उठाएगी। यह फंड हर फैक्ट्री की गन्ना पैराई क्षमता और आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) के जरिए दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है कि जब राज्य की चीनी मिलें भारी आर्थिक संकट से जुझ रही हैं और उन पर पिछले पैराई सीजन का किसानों का लगभग 200 करोड़ का बकाया है। इस फंड से मिली को बकाया चुकाने और आने वाले पैराई सीजन के लिए आसानी से तैयारी करने में मदद मिलेगी।

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ घटना पर खड़गे का नड्डा को पत्र, एफआईआर की मांग

नई दिल्ली, एंजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्देश दें कि वे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं जो पिछले महिने हल्द्वानी में खड़गे की रैली वाली जगह को कथित तौर पर शुद्ध करने में शामिल थे। खड़गे ने 2 सितंबर को लिखे पत्र में नड्डा को राज्यसभा में दिए गए उनके उस आशवासन की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खड़गे ने हिंदी में लिखे अपने पत्र में कहा कि आपको यह होना कि 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में, मैंने बहुत दुख और पोड़ा के साथ, 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी में हुई अपनी जनसभा के बाद छुआछूत से जुड़ी ‘शुद्धिकरण’ की घटना का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि मेरी बात के जवाब में आप सदन में खड़े हुए और कहा, ‘महोदय, माननीय खड़गे जी ने

जो कहा है, वह सचमुच बहुत दुखद विषय है। यह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दुखद है, बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। जो कुछ भी हुआ है, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी

गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसकी पूरी जांच करेंगे। आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वह हम सभी के लिए खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि नड्डा ने सदन को यह भी भरोसा दिलाया था कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति (सी.पी. राधाकृष्णन) ने भी इस घटना पर दुख जताया। खड़गे ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि घटना के 24 दिन बाद भी, इसमें कथित तौर पर शामिल संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि इस घटना का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह था कि रामलीला मैदान में, जहां मैंने रैली को संबोधित किया था।

नाम कट जाने से राज्यसभा सदस्यता पर था खतरा

नई दिल्ली, एंजेंसी। पंजाब SIR से राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी



आर्यावर्त क्रांति

'संवाद और कूटनीति से ही संघर्षों का समाधान संभव'

पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक वृद्धि को सराहा

नई दिल्ली, एंजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के जल्द समाधान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति से ही संघर्षों का समाधान संभव है। पीएम मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही।

पीएम मोदी ने कहा, 'आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। भारत और बेल्जियम, दोनों ही देश कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष के जल्द समाधान और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। आतंकवाद को उसके सभी रूपों में जड़ से खत्म करना, हमारी साझा प्रतिबद्धता है।'

पीएम मोदी ने वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की तारीफ की और कहा कि यह देश की विकास यात्रा में दुनिया के विश्वास का स्रोत है। पीएम मोदी ने कहा, 'इस समय दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और अनिश्चितता खाद्य और ईंधन को लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने गति बनाए रखी है। हमने पिछली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। आज भारत की विकास गाथा दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।'

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ घटना पर खड़गे का नड्डा को पत्र, एफआईआर की मांग

नई दिल्ली, एंजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्देश दें कि वे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं जो पिछले महिने हल्द्वानी में खड़गे की रैली वाली जगह को कथित तौर पर शुद्ध करने में शामिल थे। खड़गे ने 2 सितंबर को लिखे पत्र में नड्डा को राज्यसभा में दिए गए उनके उस आशवासन की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खड़गे ने हिंदी में लिखे अपने पत्र में कहा कि आपको यह होना कि 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में, मैंने बहुत दुख और पोड़ा के साथ, 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी में हुई अपनी जनसभा के बाद छुआछूत से जुड़ी ‘शुद्धिकरण’ की घटना का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि मेरी बात के जवाब में आप सदन में खड़े हुए और कहा, ‘महोदय, माननीय खड़गे जी ने

जो कहा है, वह सचमुच बहुत दुखद विषय है। यह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दुखद है, बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। जो कुछ भी हुआ है, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लॉ स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार बीसीआई के पास नहीं

नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े उस आदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि BCI और राज्य बार काउंसिलों के पास लॉ स्टूडेंट्स के व्यवहार को रेगुलेट करने की कानूनी शक्ति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संस्थाएं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती हैं जब वे एडवोकेट के तौर पर एनरोल हो जाएं। ये टिप्पणियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सुर्य कांत और जस्टिस जयमाल्य बागची और बी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उनके संबंधित विश्वविद्यालयों या संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उनके अपने नियमों और विनियमों के तहत होता है। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'यह अधिकार उस विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के पास होता है जिसमें छात्र नामांकित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया

कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित और लागू कर सकती है, जो कानूनी प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार हो। हालाँकि, वह किसी लॉ छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस सब की शुरुआत BCI के 13 अगस्त के उस आदेश से हुई जिसमें कहा गया था कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को राज्य बार काउंसिल्स में एनरोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कांते के शामिल होने का विरोध किया था। हालाँकि, बाद में भारी विवाद के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया।

आकाश आनंद को मैच्योर होने की जरूरत, अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं... भतीजे को लेकर मायावती का बड़ा बयान

मायावती ने आकाश आनंद अपरिपक्व बताया: उन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल नहीं दी जाएगी

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर झटका दिया है। मायावती ने आज की महत्वपूर्ण बैठक में साफ कहा कि आकाश आनंद में अभी पर्याप्त परिपक्वता नहीं आई है। मायावती के अनुसार, जब तक वह और ज्यादा मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि इस बैठक में आकाश आनंद को भी नहीं बुलाया गया था।

यह उनके लिए इस तरह का तीसरा बड़ा झटका है, जिसके बाद BSP में उनकी भूमिका और राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। BSP की



देश की विकास यात्रा में दुनिया के विश्वास का स्रोत है। पीएम मोदी ने कहा, 'इस समय दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और अनिश्चितता खाद्य और ईंधन को लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने गति बनाए रखी है। हमने पिछली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। आज भारत की विकास गाथा दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।'



जो कहा है, वह सचमुच बहुत दुखद विषय है। यह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दुखद है, बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। जो कुछ भी हुआ है, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी



अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उनके संबंधित विश्वविद्यालयों या संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उनके अपने नियमों और विनियमों के तहत होता है। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'यह अधिकार उस विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के पास होता है जिसमें छात्र नामांकित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया



राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई थी।

किन विषयों पर केंद्रित रही बैठक?

इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे अहम राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुख्य रणनीतियों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मायावती चुनाव वाले राज्यों के नेताओं से वहां के बदलते राजनीतिक हालात पर सीधे फीडबैक

आर्यावर्त क्रांति

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर आगमन के बाद स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह पहुंचकर इसका भव्य लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान प्रसाद धानुका विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगीत से हुआ। इसके बाद ब्रज के कलाकारों ने राधा-कृष्ण की लीलाओं का मनमोहक मंचन किया। समारोह में गुजरात के गरबा और ब्रज के प्रसिद्ध मयूर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं। लोकार्पण से पूर्व मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण के स्वरूप में सजे-धजे नन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराकर उन्हें

गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसकी पूरी जांच करेंगे। आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वह हम सभी के लिए खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि नड्डा ने सदन को यह भी भरोसा दिलाया था कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति (सी.पी. राधाकृष्णन) ने भी इस घटना पर दुख जताया। खड़गे ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि घटना के 24 दिन बाद भी, इसमें कथित तौर पर शामिल संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि इस घटना का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह था कि रामलीला मैदान में, जहां मैंने रैली को संबोधित किया था।

नाम कट जाने से राज्यसभा सदस्यता पर था खतरा

नई दिल्ली, एंजेंसी। पंजाब SIR से राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक बदले की भावना से झापट वोटर लिस्ट जारी की है। खूद राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया है। जो सूची जारी की गई है उसमें उन्हें शिफ्टेड दिखाया गया है। इस खबर के आते ही एक दावा किया जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा का नाम SIR से कट गया तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर खतरा आएगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर SIR की फाइनल लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कट भी जाए तब भी

'स्कूल ठीक करो' अभियान का क्यों करते हैं विरोध?: अभिजीत दीपके का भाजपा पर हमला

नई दिल्ली, एंजेंसी। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान 'स्कूल ठीक करो' अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेहतर स्कूल और शिक्षा का मुद्दा किसी एक राजनीतिक पार्टी या संगठन का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

अभिजीत दीपके ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ-साथ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कर रही हैं। ऐसे में जो भी लोग चाहते हैं कि देश के स्कूल अच्छे हों, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल

उठाया कि जब भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात होती है, तो भाजपा के

विपक्षी पार्टियों पर साधा था निशाना

आकाश आनंद ने 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद में जनसभा कर पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया। अपनी उम्र 30 साल बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव करीब 50 साल के हैं, इसलिए उन्हें अंकल कहना अनादर नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है। 2024 में उनके एक बयान को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मायावती ने उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी की जिम्मेदारियों से हटा दिया था। बाद में उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई।

लेने और फिर उनके इनपुट के आधार पर राज्य-विशेष रणनीतियों पर चर्चा हुई। राज्य इकाइयां पार्टी प्रमुख को जिला और वृथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में आ रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी



उपहार भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने ब्रज के प्रमुख संतों फूलडोल बिहारी दास महाराज, महंत सुतीशदास, महंत सनतकुमार शरण महाराज, स्वामी रामदेवानंद सरस्वती और संत बलराम दास का स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान 321 सपेरा

समाज के लाभार्थियों को भवन आवंटन पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

ब्रज में तेजी से बदल रही विकास की तस्वीर

पूर्व मंत्री व विधायक श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा

कि ब्रज से लेकर गोरखपुर तक सतत विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, रयोंगी बाबा आयो है, एक हजार इक्कावन करोड़ रुपैया लायौ है। वर्ष 2017 से पहले ब्रज की स्थिति जर्जर थी, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में यमुना में गिरने वाले मथुरा के 36 में से 32 नालों को बंद कर दिया गया है और शेष 4 नाले भी अक्टूबर तक पूरी तरह बंद हो जाएंगे। साथ ही सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना और ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग पर पड़ाव स्थलों के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि- आम आदमी पार्टी सरकार ने अब बदले की राजनीति को झापट वोटर लिस्ट तक पहुंचा दिया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये झापट वोटर लिस्ट है। इस पर दावा और आपत्ति अभी बाकी हैं। सांसद ने कहा कि वह अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली फाइनल लिस्ट में अपना नाम वापस दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं। पंजाब SIR में नाम कट जाने से एकदम से ये दावा किया जाने लगा कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसी साल उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी के बाद से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच बयानबाजी चल रही है। ये तब और बढ़ गई जब पंजाब SIR की झापट

राघव चड्ढा का नाम कट जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अब बदले की राजनीति को झापट वोटर लिस्ट तक पहुंचा दिया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये झापट वोटर लिस्ट है। इस पर दावा और आपत्ति अभी बाकी हैं। सांसद ने कहा कि वह अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली फाइनल लिस्ट में अपना नाम वापस दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं। पंजाब SIR में नाम कट जाने से एकदम से ये दावा किया जाने लगा कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसी साल उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी के बाद से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच बयानबाजी चल रही है। ये तब और बढ़ गई जब पंजाब SIR की झापट



उठाया कि जब भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात होती है, तो भाजपा के

लोग इसका विरोध क्यों करने लगते हैं। क्या भाजपा को नहीं लगता कि

'आप' को राहत : सत्येंद्र जैन को कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी ने किया था गिरफ्तार

नई दिल्ली, एंजेंसी। राजज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन को डीजेबी एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में जमानत दे दी है। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने इसी मामले में गिरफ्तार किए था। सत्येंद्र जैन को दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के टेंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले

जन्माष्टमी से पहले मुख्यमंत्री योगी ने ब्रजवासियों को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, 7240 लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा पहुंचकर ब्रजवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया और संतों को सम्मानित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र, चेक और चाबियां प्रदान कीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 (शहरी) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7240 लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की।

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने एक लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वाले सेपरा संवर्ग के

गोमतीनगर में मकान से टोटी, शावर सेट और फिटिंग्स चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोमतीनगर थाना पुलिस ने मकान में घुसकर टोेटियां, शावर सेट, पंखे, मोटर और अन्य फिटिंग्स चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के साथ मौजूद करीब 17 वर्षीय एक बाल अपचारी को भी नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया है। दोनों के कब्जे से चोरी की गई विभिन्न सामग्री बरामद की गई है।पुलिस के अनुसार 2 सितंबर 2026 को शैलेश मिश्रा पुत्र डॉ. एसबी मिश्रा, निवासी नोड्डा, मूल निवासी विकास खंड, गोमतीनगर, लखनऊ ने गोमतीनगर थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनके मकान में अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने प्रवेश कर वहां लौी टोेटियां, शावर सेट तथा अन्य फिटिंग्स को खोलकर चोरी कर लिया

है। तहरीर के आधार पर गोमतीनगर

थाने में मुकदमा अपराध संख्या 394/2026, धारा 305A/331(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रेम कुमार द्वारा की जा रही थी।

घटना के शीघ्र खुलासे और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए गोमतीनगर थाना पुलिस टीम ने लगातार सुरागरसी-पतारसी की।

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर संदिग्धों की तलाश शुरू की।इसी क्रम में 3 सितंबर 2026 को उपनिरीक्षक प्रेम कुमार, उपनिरीक्षक जसीम रजा, हेड कांस्टेबल बब्बन यादव और कांस्टेबल सुनील यादव क्षेत्र में गश्त एवं तलाश में मामूर थे।

नाबालिग से दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।पुलिस के अनुसार 2 सितंबर 2026 को पीड़िता के पिता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी करीब 17 वर्षीय पुत्री की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया तथा उसके साथ



शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया।मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 601/2026 दर्ज किया। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 64(1), 351(3), 115(2), पाक्सो अधिनियम की

धारा 3/4 तथा सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम की धारा 66 ई के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने 3

सितंबर 2026 को मामले में नामजद

आरोपी शिवम रावत पुत्र रामसेनही रावत, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी बुद्ध खेड़ा, माजरा बरोना, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना सुशांत गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और ऐसे मामलों में आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है।

लखनऊ समाचार

सड़क दुर्घटना में घायल 31 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दूसरे वाहन से टकराई

लखनऊ। आशियाना थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 31 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राम बाकी पुत्र राधा चरण, निवासी उमरा, थाना गंग, जनपद डींग, राजस्थान के रूप में हुई है। वह लखनऊ स्थित होटल वीनस में कार्य करता था।पुलिस के अनुसार 2 सितंबर 2026 को सुबह करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पावर हाउस चौराहे के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही आशियाना थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए लोकबंधु अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पीएम फसल बीमा योजना, हर किसान के लिए किफायती फसल बीमा

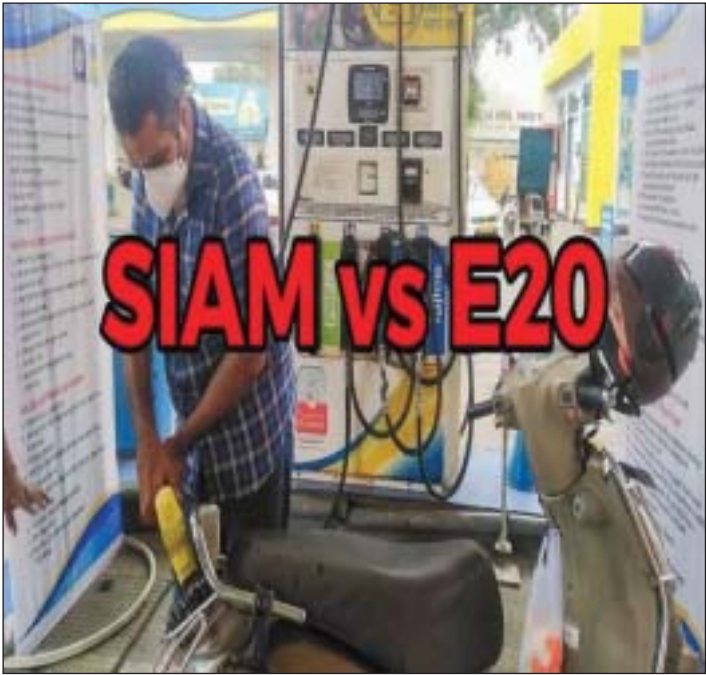
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पूरे देश में सुखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों, बीमारियों, वुआई न हो पाने, स्थानीय आपदाओं, जलभराव से होने वाले नुकसान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और फसल कटाई के बाद होने वाले खास नुकसानों के खिलाफ व्यापक कवरेज देती है। 2026–27 के लिए ₹12,200 करोड़ के आवंटन के साथ, पीएमएफबीवाई किसानों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता को मजबूत बानाे, उनकी आजीविका की रक्षा करने, आय को स्थिर करने और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का काम जारी रखे हुए है। पिछले 10 वर्षों में, खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर रबी 2025–26 तक, 92.46 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और 26.33 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों के लिए ₹2.06 लाख करोड़ से ज्यादा के दावों का भुगतान किया गया है। तकनीक पर आधारित पहलों, जैसे कि 'प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली' (वाईईएस-टेक) और 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (डब्ल्यूआईएनडीएस) को शामिल करने से दावों का निपटारा तेज, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी हो गया है, जिससे यह योजना और भी मजबूत हुई है।

फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल के नुकसान से बचाता है। समय पर मिलने वाला मुआवजा किसानों को आय में अचानक आई कमी से निपटने, नुकसान की भरपाई करने, कर्ज चुकाने और अगली फसल के मौसम में निवेश करने में मदद करता है। यह खेती की क्षमता को मजबूत करता है, आजीविका की रक्षा करता है और अनिश्चित स्थितियों में भी कृषि उत्पादन को जारी रखने में मदद करता है। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाया जा सके। इसमें बुवाई से पहले के जोखिम (जैसे बुवाई न हो पाना या बुवाई का विफल होना), मौसम के बीच में बड़े पैमाने पर खराब हालात, ओलावृष्टि, बाढ़, भूखलन जैसी स्थानीय आपदाएं (अलग-अलग खेतों के स्तर पर), और फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश और अन्य तय खतरों से होने वाले नुकसान शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम की दरें कम और किफायती रखी गई हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026–27 में पीएमएफबीवाई के लिए ₹12,200 करोड़ आवंटित किए हैं, जो फसल बीमा और किसानों को सुरक्षा देने के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

असम के नागांव जिले के चनखला गांव के रहने वाले छोटे किसान अनवर हुसैन अपने परिवार की आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। जब भारी बारिश से उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, तो उन्हें अपने कर्ज चुकाने और अगली बुआई के लिए पैसे जुटाने को लेकर चिंता सताने लगी। अच्छी बात यह थी कि अनवर ने सिर्फ ₹100 का मामूली प्रीमियम देकर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) में अपना पंजीकरण कराया हुआ था। फसल के नुकसान का आकलन होने के बाद, उन्हें इस योजना के तहत ₹50,600 का मुआवजा मिला। समय पर मिली इस आर्थिक मदद से उन्हें नुकसान से उबरने, अपना कुछ कजर चुकाने और अगले सीजन के लिए खेती का जरूरी सामान खरीदने में मदद मिली। इस मदद की वजह से, आर्थिक तंगी में फंसने के बजाय अनवर नए आत्मविश्वास के साथ खेती जारी रख पाए। आज, वह अपने गांव के दूसरे किसानों को भी अपनी फसल का बीमा कराने के लिए जोरदार तरीके से प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि पीएमएफबीवाई मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। पीएमएफबीवाई फसल के नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देता है और किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। यह आधुनिक खेती के तरीकों, फसल विविधीकरण और उत्पादन से जुड़े जोखिमों का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। पीएमएफबीवाई तय पात्रता शर्तों के आधार पर किसानों (जिसमें किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार किसान भी शामिल हैं) को व्यापक फसल बीमा कवरेज देता है। किसानों के पास बीमा योग्य हित, जमीन के वैध दस्तावेज या पट्टे के समझौते या राज्य-विशेष की पहले से तय जरूरतों के अनुसार बुवाई के प्रमाण-पत्र होने चाहिए और उन्हें तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। जोखिम का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएफबीवाई खेती से जुड़े सभी तरह के किसानों—चाहे उन्होंने ऋण लिया हो या नहीं—को कवर करता है। गैर-ऋणी किसान वे होते हैं जिन्होंने फसल के लिए कोई ऋण नहीं लिया है या जिनके पास नॉन-स्टैंडर्ड किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जुड़े ऋण हैं।

व्यंग्य

साख में भी सेंध लगेगी



सियाम के पलटने से सिर्फ उसकी ही संदिग्ध नहीं हुई है, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठे हैं। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि क्या सियाम पर सरकार ने दबाव डाला, जैसाकि आरोप लग रहे हैं?

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने पहले सरकार को पत्र लिखकर शिकायत की कि ई-20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिले) पेट्रोल से कारें खराब हो रही हैं। लेकिन अब सियाम ने यह कहते हुए वो पत्र वापस ले लिया है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अभी और जानकारी की जरूरत है! ई-20 ईंधन को बड़ा सियासी मुद्दा बना चुके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि कार कंपनियों के इस संगठन ने सरकार के दबाव में आकर पत्र वापस लिया। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने सियाम के दोनों पत्रों में मौजूद 'खतरनाक' अंतर्विरोधों का उल्लेख करते हुए कहा है कि दबाव में हुए इस रुख परिवर्तन से भारतीय ऑटो उद्योग की प्रमुख संस्था की साख नष्ट हुई है।

अपने पहले पत्र में सियाम ने लिखा था- 'कारों में क्लोराइड प्रेसर के कारण पाट-पुर्जों को बदलने के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा होने का संबंध ईंधन से पाया गया है।' बहरहाल, अपने इस अफसोसनाक है कि उसने इस मामले में भी धुआंधार प्रचार से शिकायत पर परदा डालने और तथ्यों को छिपाने का नजरिया अपनाया है। मगर ऐसे तरीके अब कारगर होते नहीं दिखते। असल में सियाम के पलटने से सिर्फ उसकी ही संदिग्ध नहीं हुई है, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठे हैं। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि क्या सियाम पर सरकार ने दबाव डाला, जैसाकि आरोप लग रहे हैं? अगर ये संदेह मजबूत हुआ, तो उससे सरकार की साख में भी सेंध लगेगी।

देश की बाकी आबादी को भी सोचने मजबूर किया

अजीत द्विवेदी

चुनावी राजनीति का विमर्श बदल रहा है। कॉंक्रिट जनता पार्टी यानी सीजेपी भले राजनीतिक दल नहीं बनी है और बने तो हो सकता है कि कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसने देश के राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन ने एक नए विमर्श को जन्म दिया है, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लायमेंट और एनर्जी यानी 'ट्रिपल ई' केंद्र में हैं। इससे पहले राजनीति का विमर्श जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के इर्द गिर्द घूमता था। उसमें भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा भी जरूरत के हिसाब से शामिल होता था। लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय भावनाओं या उप राष्ट्रीयता की भावना के इर्द गिर्द चुनाव का ताना बाना बुना जाता था। इसी आधार पर मुद्दे तय किए जाते थे, उम्मीदवारों का चयन होता था और नेताओं के भाषण होते थे। अब इसमें बदलाव आ रहा है। विमर्श के नए मुद्दे आ रहे हैं और नेताओं के भाषण बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपवाद हैं, जिनका भाषण अब भी बाबर, औरंगजेब, सालार गाजी या व्यापक रूप से मुस्लिम विरोध के इर्द गिर्द होता है।

बहरहाल, देश के बदलते राजनीतिक विमर्श को दो हिस्सों में बांट कर देखने की जरूरत है। पहला हिस्सा तो वह है, जो जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान युवाओं के आक्रोश में अभिव्यक्त हुआ। युवा जिन्दा अंदोज में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और बिना किसी शर्मिंदगी के प्रधानमंत्री तक को निशाना बना रहे थे वह एक पहलू है। उससे नेताओं और पार्टियों को लगा और यह सही भी है कि एक नई पीढ़ी अपनी खास पहचान के साथ राजनीतिक क्षितिज पर उभरी है। उसने जाति, धर्म, क्षेत्र और यहां तक कि लिंग की पहचान छोड़ दी है। उसे 'जेन जी' की पहचान दी गई और उसे एंड्रेस करने की कोशिश शुरू हुई। मुश्किल यह है, तब ज्यादातर नेता उनके आचार, व्यवहार, भाषा और सरोकार को नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने 'जेन जी'को समझने का अपना एक स्टैरियोटाइप विकसित किया और उन्हें उसी से देखना शुरू किया।

अगर नेता अपने परिवार में देखते और अपने बच्चों के व्यवहार से 'जेन जी'को समझने का प्रयास करते तो उनको पता चलता कि वे 'जेन जी' को लुभाने के लिए वे जो कर रहे हैं वह कितना पैथेटिक

ब्लॉग

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले



डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपयोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास और संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं, जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग,

और ऑफ द मार्क है। 'जेन जी' को लुभाने के लिए नेता को प्रयास कर रहे हैं उससे वे एक पूरी पीढ़ी को शर्मिदा कर रहे हैं और खुद एक मूर्ख के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए उनको यह प्रयास बंद करना चाहिए और इस पीढ़ी की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे या उनके सरोकारों को समझना चाहिए। यही बदलते राजनीतिक विमर्श का दूसरा पहलू है। वह मुद्दों और सरोकारों से जुड़ा है। वह सरोकार 'ट्रिपल ई' का है। तभी एजुकेशन, एम्प्लायमेंट और एनर्जी पर युवाओं व देश के लोगों के सरोकारों को समझने की जरूरत है। दिल्ली से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र व बिहार तक ये ही मुद्दे अभी विमर्श का मुख्य विषय हैं। इसमें 'जेन जी' और 'जेन अल्फा' दोनों शामिल हैं। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, शिक्षक की कमी है, समय पर शिक्षक नहीं आते हैं, स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ाई का कैलेंडर फॉलो नहीं किया जाता है, समय पर परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, इन तमाम मुद्दों पर छात्र आंदोलित नहीं होते थे। किन अब तस्वीर बदल गई है। अब स्कूली बच्चे भी ये मुद्दे उठा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वे अपने अभिभावकों के सामने नहीं, बल्कि सड़क पर उतर कर ये मुद्दे उठा रहे हैं। मजबूरी में नेताओं और राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। अभी तो सिर्फ बात हो रही है और आशवासन दिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आशवासनों को पूरी भी करना होगा।

दूसरा सरोकार एम्प्लायमेंट यानी नौकरी और रोजगार का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेहतर जीवन स्तर के लिए या कमजोर आर्थिक तबके के लोगों के सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में ऊपर आने के लिए सम्मानजक नौकरी से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। परंतु पिछले कुछ समय से अलग अलग कारणों से नौकरी और रोजगार दोनों में लगातार कमी होती जा रही है। इसका नतीजा नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाई दिया, जिसमें कहा गया है कि 15 से 29 साल की उम्र के 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न किसी कोशल का प्रशिक्षण ले रहे हैं और न कोई नौकरी कर रहे

हैं। यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन 8.7 करोड़ युवाओं के अलावा इसी उम्र वर्ग के इससे कम से कम दोगुने युवा पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी व रोजगार हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वे भी अब तक नौकरी आने का इंतजार करते थे और पेपर लोक या परीक्षा में गड़बड़ी या परीक्षा में धांधली या परीक्षा रद्द होने को निर्यात मान कर चुप बैठे रहते थे। लेकिन अब उनकी चुप्पी टूटी है। जंतर मंतर के प्रदर्शन ने उनको रास्ता दिखाया है। वे नौकरी के हर विज्ञापन को बारीकी से देख रहे हैं। उसकी कमियां सामने ला रहे हैं। सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि वह नौकरी या दाखिले के लिए होने वाली प्रतिযোগिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करें और उसका पूरी तरह से पालन करें। वैकेंसी बढ़ाने से लेकर परीक्षा कराने के तरीके पर छात्र सरकारों से बात कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या सवा चार लाख से दोगुनी होकर साढ़े आठ लाख हो गई है। ऐसी ही स्थिति राज्य सरकारों की भी है। युवा अब इसको मुद्दा बना रहे हैं।

तीसरा सरोकार एनर्जी का है। शिक्षा और नौकरी तो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन एनर्जी उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन यह भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि हाल की कई घटनाओं ने ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत की कमजोरियों को जाहिर किया है। ईरान और अमेरिका की जंग ने आपूर्ति के संकट को उजागर किया तो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों को होने वाले नुकसान की जानकारी भी लोगों को मिली और इथेनॉल मिश्रण से खाद्यान्न संकट का जो दौर आया, उसकी भी एक झलक लोगों को मिली।

अगर शिक्षा व नौकरी ने युवाओं को आंदोलित किया तो ऊर्जा की बढ़ती कीमत, आपूर्ति के संकट, गाड़ियों के इंजन की परेशानी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और संभावित खाद्यान्न संकट ने युवाओं के साथ साथ देश की बाकी आबादी को भी सोचने पर मजबूर किया। इसका असर यह हुआ है कि सरकारें भी स्वच्छ ऊर्जा को लेकर गंभीर हुई हैं तो इथेनॉल मिश्रण को कम करने पर भी विचार हो रहा है। अगर ये सरोकार लंबे समय तक राजनीतिक विमर्श में टिकते हैं और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं तो देश में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

भारत का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। आज दुनिया चीन के विकल्प के रूप में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की तलाश कर रही है। भारत के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी विशिष्ट ताकतें हैं। यदि भारत विनिर्माण, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं में अपनी क्षमता बढ़ाता है, तो वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। 2047 का विकसित भारत केवल सरकार का संकल्प नहीं, बल्कि देशवासियों की सामूहिक आकांक्षा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर इस यात्रा में एक उत्साहजनक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भारत को लगातार उच्च विकास दर, मजबूत वित्तीय व्यवस्था और स्थिर आर्थिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, कोशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना होगा।

भारत की आर्थिक कहानी अब केवल आंकड़ों की कहानी नहीं रह गई है। यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की कहानी बन रही है। दुनिया जब युद्ध और आर्थिक अस्थिरता की छाया में अपनी दिशा तलाश रही है, तब भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन उसे एक भरोसेमंद और संभावनाशील शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने यह संदेश दिया है कि वैश्विक संकटों के बीच भी उसकी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियों और योजनाओं को अब आगे ले चलने में अधिक रोजगार, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन और अधिक समान अवसरों से जोड़ना होगा। भारत के आर्थिक आकाश पर उगता यह उजाला तभी स्थायी प्रकाश बनेगा, जब विकास की रोशनी देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन तक पहुंचे। यही 2047 के विकसित भारत की वास्तविक कसौटी होगी और यही आर्थिक शक्ति को जनशक्ति में बदलने का मार्ग भी।

झारखंड में पावर प्लांट के नाम पर 290 करोड़ का

घोटाला, कोलकाता में 11 ठिकानों पर ईडीकी रेड

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईडी ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ED की कोलकाता जोन-1 टीम ने करीब 290 करोड़ रुपये के बैंक प्रॉड मामले में कोलकाता के 11 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ये मामला M/s Kohinoor Power Pvt। Ltd। से जुड़ा है। कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए बैंकों से लोन लिया था। आरोप है कि कंपनी ने लोन की रकम का इस्तेमाल पावर प्लांट के बजाय अन्य ग्रुप कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करने और निजी इस्तेमाल में किया।

बाद में कंपनी NCLT में चली गई। लिक्विडेशन की प्रक्रिया के दौरान महज करीब 7 करोड़ रुपये ही रिकवर हो सके, जिससे

बैंकों और अन्य लेनदारों को भारी नुकसान हुआ। ED की तलाशी में ग्रुप के प्रमोटर प्रशांत बोथरा और विजय बोथरा से जुड़े परिसरों को भी कवर किया जा रहा है।

नकली टोल वसूलने पर ईडी की छापेमारी

2 सितंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) धोखाधड़ी मामले में पश्चिम बंगाल समेत सात राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की। इस मामले में नकली टोल रसीदें जारी करके वाहन चालकों से गैर-कानूनी तरीके से पैसे वसूले गए थे। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ED के 6 अधिकारियों की एक टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कोलकाता के शेक्सपियर सरणी

इलाके में एक फ्लैट पर छापा मारा। यहां शहर के एक व्यापारी का ऑफिस है। ED सूत्रों ने बताया कि एजेंसी लखनऊ (UP) में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही थी।

जांच में पता चला कि फर्जी रसीदें जारी करके पैसे इकट्ठा किए गए और टोल वृथ से चालाकी से पैसे हटा भी लिए गए। सूत्रों का कहना है कि टोल पर मौजूद सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे पैमेंट मिलने का कोई ब्यौरा नहीं था। जांच करने वाले अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया पैसा कहाँ गया और इस धोखाधड़ी में कौन-कौन शामिल था।

कोलकाता में सुबह 4.30 बजे भारी बवाल

कैमक स्ट्रीट टीएमसी दफ्तर पर हमला, अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। तुणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में BJP कार्यकर्ताओं ने सुबह करीब 4:30 बजे कोलकाता की कैमक स्ट्रीट पर TMC ऑफिस पर हमला किया। तोड़-फोड़ की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। जब बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा कर रहे थे तो कोलकाता पुलिस तकरीबन 2 घंटे तक कार्रवाई करने में नाकाम रही है।

अभिषेक बनर्जी ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगरअगर लोग सुबह 4:30 बजे हथियारों के साथ किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में घुस सकते हैं, लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं और



तोड़-फोड़ कर सकते हैं, जबकि पुलिस वहां मौजूद नहीं होती, तो पश्चिम बंगाल में कानून का शासन आखिर बचा ही क्या है? अब बहुत हो चुका। दोषियों को गिरफ्तार करें, जवाबदेही तय करें। अभी कार्रवाई करें। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कि वे लगभग दो घंटे तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहे हमारे लोगों और वकीलों की ओर से बार-बार कॉल और ईमेल

किए जाने के बावजूद, लगभग दो घंटे तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह बहुत ही गलत और अस्वीकार्य है हम इस हमले में शामिल हर व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी या हथियारों से लैस गुंडों का कोई भी समूह कानून से ऊपर नहीं हो सकता।

अभिषेक बनर्जी ने जांच की मांग की

अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हमारे लोगों पर हमला कर उनके फोन छीन लिए गए।फर्नीचर तोड़ा, ऑफिस में तोड़-फोड़ की और इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट कर दिया गया। हम इस घटना की भी जांच की मांग करते हैं कि

इस हिंसा की योजना किसने बनाई, इसे किसने आयोजित और निर्देशित किया, और बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में क्यों नाकाम रही।

अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की अपील की

अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आज सुबह-सुबह BJP ने मेरे पार्टी ऑफिस के साथ जो किया क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर इसपर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या केंद्रीय गृह मंत्री कार्रवाई करेंगे? क्या PMO कार्रवाई करेगा? या वे बस अनदेखा

करते रहेंगे? अब समय आ गया है कि न्यायपालिका, खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट, इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल में कानून का शासन बनाए रखने के लिए कदम उठाए। अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आप तुणमूल कांग्रेस और मुझसे इतना क्यों डरते हैं कि आपको इस तरह की डराने-धमकाने की हरकतें करनी पड़ रही हैं? अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के जरिए ऐसा वर्तव किया जाना है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

तारा सुतारिया का बोल्ड और विंटेज अवतार, लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में दिए किलर पोज, इंटरनेट पर मचा बवाल



बॉलीवुड की स्टिंगर और ग्रेसफुल एक्ट्रेस तारा सुतारिया जब भी कैमरे के सामने आती हैं, अपने फैशन

सेंस और कालिलाना अंदाज से लाइमलाइट चुरा लेती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए

फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैस के होश उड़ गए हैं।

इस बार तारा ने 1990 के दशक के ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर और विंटेज स्टाइल को बेहद बोल्ड और मॉडर्न अंदाज में री-क्रिएट किया है। तस्वीरों में तारा टीएनए ब्रांड की लेपर्ड-प्रिंट वेलवेट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं।

इस ऑफ-शोलडर स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली ड्रेस की फिटिंग तारा के कर्क्स और परफेक्ट फिगर को बेहतरीन तरीके से हाइलाइट कर रही है। वेलवेट फैब्रिक इस बोल्ड लेपर्ड प्रिंट को एक रॉयल और लक्जरी लुक दे रहा है। आउटफिट को विंटेज टच देने के लिए तारा ने गले में पल्ट पेडेंट वाला चंकी गोल्ड चौकर नेकलेस, विंटेज इयररिंग्स और हाथों में स्टेटमेंट रिंग्स कैरी की हैं।

तारा के लुक्स और मेकअप ने इस फोटो-शूट में चार चांद लगा दिए हैं। तारा ने अपने बालों को रेड्रो साइड-स्वीपड सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया है, जो क्लासिक हॉलीवुड एक्ट्रेसों की याद दिलाता है।

विंउ आइलाइनर, शेडेड आई-शैडो, न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक और परफेक्टली स्कल्टेड कंटूरिंग तारा के चेहरे के फीचर्स को बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तारा सुतारिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेड कर रही हैं और फैस उनके इस वाइल्ड, बोल्ड और विंटेज अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कार्ति की 'सरदार 2' का ट्रेलर जारी, दमदार एक्शन और रोमांचक कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता, फिल्म 10 सितंबर को होगी रिलीज

दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता कार्ति अपनी आगामी फिल्म 'सरदार 2' के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। पी.एस. मित्रन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर निर्माताओं ने जारी कर दिया है। फिल्म 10 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। फिल्म के प्रचार अभियान और टीजर को पहले ही दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल चुकी है।

ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, रोमांच और शानदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कार्ति को एक गुप्त मिशन पर निकले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। कहानी में रहस्य और रोमांच के साथ कई बड़े मोड़ नजर आ रहे हैं। वहीं, अभिनेता एस.जे. सूर्या के साथ कार्ति की पिंडित ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

'सरदार 2' के ट्रेलर में बड़े स्तर पर फिल्माए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रभावशाली दृश्यांकन देखने को मिलता है। फिल्म का पार्श्व संगीत भी ट्रेलर के रोमांच को बढ़ाता है। वहीं, छायांकन ने फिल्म के दृश्यों को भव्य रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह इसलिए भी है, क्योंकि यह लोकप्रिय फिल्म 'सरदार' की अगली कड़ी है। पहली फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और अब इसके दूसरे भाग से भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं। फिल्म में मालविका मोहनन मुख्य

अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगी। उनके अलावा आशिका रंगनाथ और योगी बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का संगीत सैम सी.एस. ने तैयार किया है। इसका निर्माण प्रिंस पिक्चर्स के बैनर तले एस. लक्ष्मण कुमार और ईशान सक्सेना कर रहे हैं।

'सरदार 2' को तेलुगु भाषा में भी दर्शकों तक पहुंचाया

जा रहा है। तेलुगु संस्करण का प्रदर्शन अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर के तहत किया जाएगा।

ट्रेलर में नजर आ रहे एक्शन, कार्ति का अलग अंदाज और एस.जे. सूर्या के साथ उनकी टक्कर को देखते हुए 'सरदार 2' के प्रति दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

